नईदुनिया

चीन बना दुनिया के लिए खतरा : तिब्बत में भूकंप के पीछे चीन का हाथ, 8 लाख पर मंडराया खतरा

बीजिंग

चीन सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। तिब्बत में आए इस भूकंप ने एक बार फिर चीन की इस क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाने की योजना को सवालों के घेरे में ला दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो परोक्ष रूप से इस भूकंप के पीछे की वजह चीन के डैम प्रोजेक्ट हो सकते हैं। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 9:05 बजे (0105 जीएमटी) आया, जिसका केंद्र टिंगरी में 10 किमी (6.2 मील) की गहराई पर था। टिंगरी एक ग्रामीण काउंटी है जिसे माउंट एवरेस्ट के उत्तरी प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्विस ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई। बता दें कि तिब्बत में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से करीब 126 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटके पड़ोसी नेपाल, भूटान और भारत में भी महसूस किए गए।

भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) उत्तर में था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 1950 से अब तक ल्हासा ब्लॉक में 6 या उससे अधिक तीव्रता के 21 भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भूकंप 2017 में मेनलिंग में आया 6.9 तीव्रता का भूकंप था।

2015 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें देश के अब तक के सबसे भयानक भूकंप में लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। मृतकों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में हिमस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 18 लोग मारे गए थे।

मेनलिंग तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी के निचले इलाकों में स्थित है, जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। हालांकि, बीजिंग अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन ने 6 जनवरी को कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध से भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यूज ब्रीफ

पाकिस्तान के 40 सरकारी विभागों में नहीं मिलेगी नौकरी, डेढ लाख पद खत्म

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पहले पेंशन कटौती हुई, अब डेढ़ लाख नौकरियों को खत्म करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने मंगलवार को ऐलान किया कि सरकार ने लागत में कटौती और दक्षता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख नौकरियां समाप्त करने का फैसला किया है।यानी ये पद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इससे करीब 40 सरकारी विभाग प्रभावित होंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि सरकार संबद्ध एजेंसियों की संख्या में आधी कटौती करेगी। औरंगजेब ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम संघीय सरकार के आकार को चरणबद्ध तरीके से कम कर रहे हैं। अब तक 80 विभागों को 40 में समेकित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा जून, 2025 तक इन सुधारों को पूरा करने का है। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत रिक्त पदों को खत्म कर दिया गया, जो करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के बराबर है। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते पेंशन बिल को कम करने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों और सेना कर्मियों के पेंशन लाभ में भारी कटौती करने की घोषणा की थी। पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं, जिनमें पहली बार मिलने वाली पेंशन में कटौती की गई तथा भविष्य में पेंशन में वृद्धि निर्धारित करने वाले आधार में भी बदलाव किया गया। दरअसल, पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, साथ ही यह देश नकदी संकट से जूझ रहा है।

लॉस एंजेलिस के जंगल में लगी आग, 30 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला

वाशिंगटन। लॉस एंजेलिस में जंगल में लगी आग से आसपास के इलाके में दहशत पैदा हो गई है। यह आग तेजी से फैल रही है जिससे लोग और प्रशासन दोनों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षित रहने के लिए करीब 30 हजार लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है क्योंकि उनके घर आग की चपेट में आ सकते हैं। वहीं अमेरिका की बाइडेन सरकार ने आग पर जल्द से काबू पाने के आदेश दिए हैं। राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा जान-माल का नुकसान न हो। आग की चपेट में आने वाले इलाकों के आसपास के लोगों को आग से बचने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। अभी तक आग की वजह से कितनी संपत्ति और जानी नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन प्रशासन आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है ।

तालिबान को अमेरिका दे रहा अरबों रुपए की मदद, पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन

करांची। पाकिस्तान दूसरों को टेंशन देना चाहता है लेकिन अब वह खुद ही टेंशन में है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडन प्रशासन तालिबान को अरबों रुपए की मदद दे रहा है, ताकि वह खुद को मजबूत कर दुश्मनों से मुकाबला कर सके। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी इस रिपोर्ट पर ट्वीट कर पूछा कि क्या हम सचमुच अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा तालिबान को भेज रहे हैं इसे लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मचा गया है, लेकिन इससे पाकिस्तानी आर्मी की सांसें अटक गई हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इन तालिबानियों को हर हफ्ते हमारे टैक्स के पैसे से 40 मिलियन डॉलर दिया जा रहा है एक यूजर ने लिखा- अमेरिकी होने के नाते हम इससे कैसे सहमत हो सकते हैं तालिबान हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारे ही हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वह लोग हैं जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या की और हम उन्हें लाखों रुपए बांट रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो 7 बिलियन डॉलर के हथियार वहीं छोड़ दिए थे। इतना ही नहीं, 57.6 मिलियन डॉलर का खजाना भी अमेरिका ने तालिबान को दे दिय था। तब से अब तक अमेरिकी सरकार तालिबान को पैसा भेज रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 से अमेरिका एनजीओ के जरिए 2.6 बिलियन डॉलर तालिबान को दे चुका है। अब अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडन प्रशासन तालिबान को हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर यानी करीब 3.5 अरब रुपए भेज रहा है। तालिबान पाकिस्तान को सीधे चुनौती दे रहा है। अमेरिकी हथियारों के दम पर ही पाकिस्तान में हमले कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को मदद कर रहा है।

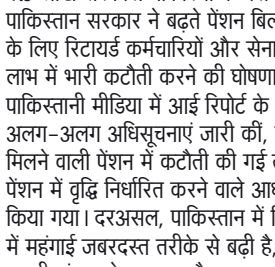

शपथ ग्रहण से पहले हमास बंधकों को करे रिहा, नहीं तो सब हो जाएगा बर्बाद

ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में सैन्य हस्तक्षेप के साथ देश नीति के भी दिए संकेत

वाशिंगटन

मिडिल ईस्ट में इस समय जंग जारी है। इजराइल-हमास युद्ध में के बीच गाजा हमलों में आम नागरिक अपनी जान गवां रहे हैं। जहां इजराइल लगातार हमले कर कर रहा है तो वहीं हमास बंधकों को रिहा नहीं कर रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लोगों को उम्मीद है कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने मिडिल ईस्ट में संभावित सैन्य हस्तक्षेप के साथ-साथ अपनी विदेश नीति के एजेंडे पर भी संकेत दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से ठीक पहले हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर उनके शपथ ग्रहण तक हमास बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं करता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बंधक परिवार फोरम ने भी अपने प्रियजनों की रिहाई के लिए ट्रंप की अटूट प्रतिबद्धता का स्वागत किया। परिवारों ने सभी पक्षों से शपथ ग्रहण से पहले एक समझौता करने का आग्रह किया।

ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए अपने नामित राजदूत स्टीव विटकॉफ को वार्ता पर लेटेस्ट जानकारी देने के लिए मंच पर बुलाया। विदेश नीति का कोई अनुभव न रखने वाले रियल एस्टेट निवेशक विटकॉफ हाल ही में मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम वार्ता का हिस्सा रहे थे। विटकॉफ ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने कुछ बहुत अच्छी प्रगति की है, और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि शपथ तक हमारे पास राष्ट्रपति की ओर से घोषणा करने के लिए कुछ अच्छी चीजें होंगी।

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने एक विशिष्ट रूप से रहस्यमय उत्तर दिया। पेंटागन का कहना है कि सशस्त्र समूह आईएसआईएल (आईएसआईएस) पर अंकुश लगाने के मिशन के तहत करीब दो हजार अमेरिकी कर्मी देश में बने हुए हैं, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपदस्थ किए जाने के बाद सीरिया में लंबे समय के लिए अमेरिकी भागीदारी के बारे में सवाल उठने लगे हैं।

अमेरिकी सैनिकों ने 2014 से पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का समर्थन किया है। क्योंकि देश में एक बहुआयामी गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति-चुनाव ने 8 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमले के बाद हमास द्वारा पकड़े गए शेष बंदियों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कठोर रुख अपनाया। इजराइल का अनुमान है कि हमास की हिरासत में करीब 100 लोग बचे हैं।

ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में दिखाने वाले नक्शे जारी कर मचाया बबाल

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने की अपनी विवादास्पद योजना को लेकर एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नया नक्शा साझा किया, जिसमें कनाडा को अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद एक और मेप जारी कर सभी को हैरान परेशान कर दिया है। इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इस बात का सबूत है कि अभी तक तो वो कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात ही कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर कनाडा संबंधी दो मैप शेयर किए हैं। इन नक्शों में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। ट्रंप के इस कदम से कनाडा में आक्रोष व्याप्त है और तीखी प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। दरअसल, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पहले एक नक्शा शेयर किया, जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया है। इस मैप के साथ उन्होंने लिखा, 'ओह कनाडा!' इसके बाद उन्होंने एक और नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा- यूनाइटेड स्टेट। अब चूंकि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को '51वां राज्य' कहते आ रहे हैं, ऐसे में नक्शों का यूं जारी करना बबाल मचाने जैसा प्रतीत हो रहा है। यही नहीं ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो कनाडा को हासिल करने के लिए 'सैन्य ताकत' का नहीं, बल्कि 'आर्थिक ताकत' का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि कनाडा और अमेरिका का एकीकरण दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने इसे आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सही कदम बताया। इससे पहले, फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने कहा था कि वह कनाडा को मिलाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इस बयान पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है।

विकलांग व्यक्ति ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए फोड़ ली अपनी आंख

बीमा कंपनी ने कराया 420 का मामला दर्ज, बेरोजगार है आरोपी

पेनांग

दुनिया में कई लोग होते हैं जो पैसे की लालच में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं कई तो हद तक पार कर जाते हैं इसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना हो या फिर खुद को। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमे का पैसा हासिल करने फर्जीवाड़ा करते हैं। तो कुछ परिजनों के इंश्योरेंस का पैसा ही हड़प जाते हैं। वहीं एक ऐसा ही मामला सामने आया है।

मलेशिया के रहने वाले एक शख्स ने इंश्योरेंस के 1 करोड़ 91 लाख रुपए हासिल करने के लिए खुद की आंख फोड़ ली। तीन बच्चों के इस विकलांग पिता को पता नहीं था कि इस मामले में वह खुद ही फंस जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 52 साल के विकलांग टैन कोक गुआन बेरोजगार हैं। ऐसे में गुआन ने आरएम1 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपए के बीमा को हासिल करने के लिए खुद की बायीं आंख फोड़ ली। बताया जाता है कि यह घटना 8 जून 2023 को मलेशिया के पेनांग के बटरवर्थ में कम्पुंग पाया में घटित हुई थी। इसके बाद टैन ने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया, ताकि पैसे को हासिल कर सकें, लेकिन कंपनी ने उल्टे टैन पर 420 का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके अलावा अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। इस मामले की सुनवाई बीते 30 दिसंबर 2024 को कोर्ट में हुई थी जहां टैन ने कंपनी द्वारा लगाए आरोपों से इनकार कर दिया था।

कोर्ट में टैन के वकील ने कहा कि वह बेरोजगार हैं और हृदय रोग सहित कई पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। अब उनकी बायीं आंख भी नहीं रही, जिससे उनकी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। टैन के वकील ने बताया कि परिवार का सारा खर्च उनकी पत्नी उठा रही हैं, क्योंकि टैन विकलांगता के कारण काम करने में सक्षम नहीं हैं।

वकील ने कोर्ट से सअनुरोध किया कि टैन को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण न्यूनतम जमानत राशि पर रिहा किया जाए। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्कील ने जांच में भी पूरा सहयोग किया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी और अब इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2025 में होगी। दूसरी ओर टैन पर लगे आरोपों की जांच चल रही है।

यिओल के कार्यालय की छत पर चढ़ा एक व्यक्ति

सियोल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक यिओल के कार्यालय की छत पर चढ़ गया एक व्यक्ति। यिलोल के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है।

तनाव के बीच पाक में 800 अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया

तालिबान का आरोप- उन प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा जिनके पास एनओसी नहीं

इस्लामाबाद

पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने सैंकड़ों अफगानों को गिरफ्तार किया है। तालिबान ने यह दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान दूतावास ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने 800 अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया है।

एक्स पर बयान में अफगान दूतावास ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए प्रवासियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास वीजा, पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) या अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) दस्तावेज हैं, जो पाकिस्तान में उनके रहने को अधिकृत करने के लिए हैं। दूतावास ने अफ़गान प्रवासियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जो हिरासत से बचने के लिए एक शर्त बन गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में उन प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, भले ही उनके पास अन्य वैध दस्तावेज़ हों। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान वापस भेजे गए लोगों में से 137 के पास वैध वीजा था, लेकिन वे एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे थे। तालिबान ने स्थिति को खराब बताया और इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारियों के दौरान महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया है। तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले अफ़गान नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और अफ़गान प्रवासियों के प्रति पाकिस्तान की नीतियों को संबोधित करने का भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्तमान में करीब तीन मिलियन अफगान प्रवासी पाकिस्तान में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने बताया कि 2024 में 1.2 मिलियन से ज्यादा प्रवासी अफगानिस्तान लौट आए हैं। बात दें अफगानिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के मुद्दे पर आमने-सामने हैं। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है।

नेपाल-भारत में वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक आज से, व्यापार-परिवहन संधि पर बनी सहमति

काठमांडू

नेपाल-भारत में 9 जनवरी से होने वाली वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक से पहले बुधवार को दोनों देशों के बीच रहे व्यापार तथा परिवहन संधि को पुनरावलोकन करने पर सहमति बन गई है। इस बैठक के लिए भारत के वाणिज्य सचिव सुशील बरथवाल काठमांडू पहुंच चुके हैं। नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल के वाणिज्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की करेंगे।

नेपाल और भारत के बीच 2009 में ही व्यापार और परिवहन संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे। तत्कालीन वाणिज्य राज्य मंत्री जयराम रमेश और नेपाल के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री राजेंद्र महतो ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इस संधि के प्रावधान के मुताबिक प्रत्येक सात वर्ष में यह स्वत: नवीकरण हो जाता है। सन् 2016 और 2023 में इसका नवीकरण हो चुका है, लेकिन नेपाल की तरफ से इसमें कई असमानताएं रहने के कारण इसके पुनरावलोकन की मांग उठाई जा रही थी। वैसे तो भारत 2020 में ही इस पर पुनरावलोकन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उस वर्ष वर्चुअल बैठक ही हो पाई थी।

नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता बाबूराम अधिकारी ने बताया कि गुरुवार से शुरू होने वाली अंतर सरकारी समूह की बैठक में व्यापार तथा परिवहन संधि पर समीक्षा करना एक प्रमुख एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि इस संधि के किन प्रावधानों को बदलना है उसको लेकर गृहकार्य चल रहा है और संभवत: शाम तक उस पर सहमति जुटा लिया जाएगा। उनके मुताबिक नेपाल की तरफ से भारत की ओर से निर्यात पर लगाई गई रोक को हटाने का प्रस्ताव हो सकता है। इसी तरह नेपाल के गुणस्तर प्रमाण पत्र को भारत की तरफ से मान्यता देने की भी मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी से होने वाली बैठक में इन सभी एजेंडा पर चर्चा की जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक नेपाल और भारत के बीच अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी सहमति हो चुकी है। इस समझौते के तहत चीन से नेपाल के रास्ते भारत में होने वाले तस्करी को रोकने के लिए कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

टेस्ला साइबरट्रक को उड़ाने के लिए चैट जीपीटी का हुआ था इस्तेमाल

लास वेगास। पुलिस ने मंगलवार को इस बात का खुलासा किया है कि ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के बाहर विस्फोट करने वाले सैनिक मैथ्यू लिवेल्सबर्गर ने हमले की योजना बनाने में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि लिवेल्सबर्गर ने हमले के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनका इरादा किसी और को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इस मामले पर चैट जीपीटी के निर्माता ओपनएआई ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके उपकरणों को जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। चैट जीपीटी हानिकारक या अवैध निर्देशों का पालन नहीं करता है। ओपनएआई ने यह भी कहा कि वे इस मामले में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। लिवेल्सबर्गर के चैट जीपीटी पर किए गए खोजों से यह सामने आया कि वह विस्फोटक का टारगेट, गोलियों की गति और एरिजोना में आतिशबाजी के कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। लास वेगास मेट्रोपोलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के शेरिफ केविन मैकमहिल ने जनरेटिव एआई के उपयोग को गेम-चेंजर बताते हुए कहा कि यह पहला मामला है जब किसी व्यक्ति ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल एक उपकरण बनाने में मदद के लिए किया है।